छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

जिले का प्रथम दैनिक समाचार पत्र स्थापना वर्ष 2020

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | गौरेला पेंड्रा मरवाही, शनिवार 17 अक्टूबर 2026 | वर्ष-07, अंक-108 पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

न्यूज इन शॉर्ट

IAS ने महिला JKAS अफसर को कहा 'गेट आउट', सरकार ने दिए जांच के आदेश



नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में IAS अधिकारी कुमार राजीव रंजन द्वारा महिला JKAS अधिकारी के खिलाफ बदसलूकी मामले में J&K सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए आवास और शहरी विकास विभाग की आयुक्त/सचिव मनदीप कौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस जांच में श्रम और रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव कुमार राजीव रंजन द्वारा गांदरबल में रोजगार विभाग की सहायक निदेशकअधिकारी बीनीश वानी के प्रति किए गए कथित कदाचार के आरोपों की पड़तालके 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

नशीली दवाओं के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरतज भगवंत मान का कड़ा संदेश



नई दिल्ली। सीएम भगवंत मान ने शुक्रवार को जालंधर में एक अहम बैठक की। यहां उन्होंने पंजाब गौ सेवा आयोग के पदाधिकारियों और राज्य भर की विभिन्न गौशालाओं के प्रबंधकों से विशेष बातचीत की।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य भर के शीर्ष नागरिक और पुलिस प्रशासन अधिकारियों की एक विशाल सभा को संबोधित किया। यह संबोधन राज्य में मादक पदार्थों के पूर्ण उन्मूलन के लिए शुरू किए गए अभियान 'वॉर ऑन ड्रगेज' के तहत किया गया था। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोरा, डॉ। बलबीर सिंह, हरदीप सिंह मुंडियन, तरुणप्रीत सिंह सौंध, डीजीपी गौरव यादव के साथ-साथ सभी जिलों के उपायुक्त (डीसी), एसएसपी, पुलिस आयुक्त और डीएसपी भी उपस्थित थे।

रिजीम चेंज पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- हम गर्व से कहते हैं ये,



नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 'सत्ता परिवर्तन' वाले बयान का जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम रिजीम चेंज करके रहेंगे। ये हम गर्व से कहते हैं। हम बदलाव लाकर रहेंगे। विपक्ष का इरादा हमेशा चुनाव के जरिए सरकार बदलने का होता है। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया था कि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का मकसद बांग्लादेश की तरह ही भारत में सत्ता परिवर्तन करना है।दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा कि अब अचानक राजनाथ सिंह आ गए सरकार को बचाने।

मासिक धर्म स्वच्छता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को अवमानना का नोटिस जारी करने की दी चेतावनी



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य निर्देशों के पालन में जानकारी न देने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी चेतावनी दी है। अधिकारियों को अदालत की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, अगर वे मासिक धर्म स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि बारे में केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देते हैं।

मिल्टन जैसे ब्रांड्स के लिए इलेक्ट्रिक फैन्स का निर्माण

3,500 लोगों को रोजगार, 152.74 करोड का निवेश

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर में यश फैन्स की नई औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया गया। ?152।74 करोड़ के निवेश से स्थापित होने वाली इस इकाई में 3,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह छत्तीसगढ़ की पहली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकाई होगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसी सोच के साथ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में ऐसे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करें। उन्होंने कहा कि यश फैन्स की यह इकाई केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं, बल्कि 3,500 लोगों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक संबल तथा बेहतर भविष्य का अवसर है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय की नई श्रृंखला भी विकसित होगी। कल-पुर्जों व्यवसायों के लिए नए अवसर बनेंगे।



देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से अपने स्टील, कोयले और बिजली के माध्यम से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। अब हमारा लक्ष्य यहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर तैयार उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया के संकल्प के अनुरूप आने वाले समय में मेड इन छत्तीसगढ़ उत्पाद देशभर के घरों तक पहुंचें, इस दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।मुख्यमंत्री ने यश फैन्स का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कंपनी को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परियोजना तेजी से धरातल पर उतरे, उत्पादन शीघ्र प्रारंभ हो और प्रदेश के युवाओं को इसका रोजगार लाभ जल्द से जल्द मिले।

लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश: नितिन



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

मांग से सियासत गरमा गई है। विपक्ष के शासन परिवर्तन वाले बयान को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसे अर्बन नक्सल के एजेंडा का हिस्सा करार देते हुए हमला बोला है।जैसे शब्दों के प्रयोग से विपक्ष का असली एजेंडा देश के सामने स्पष्ट रूप से उजागर हो गया है। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने का यह कुत्सित प्रयास अर्बन नक्सल के एजेंडे का ही हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष की लड़ाई चुनाव सुधार, स्ट्रक्र या देश के युवाओं के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाकर किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए है।

विपक्ष की लड़ाई चुनाव सुधार, स्ट्रक्र या देश के युवाओं के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि देश में ठ्ठड्डह्म्द्ध4 फैलाकर किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए है।

लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग जनादेश से होकर गुजरता है, अराजकता से नहीं। भारत की राष्ट्रभक्त जनता और भारतीय जनता पार्टी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को कभी सफल नहीं होने देंगी।

नितिन नबीन ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग जनादेश से होकर गुजरता है, अराजकता से नहीं। भारत की राष्ट्रभक्त जनता और भारतीय जनता पार्टी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को कभी सफल नहीं होने देंगी।वरिष्ठ

कनॉट प्लेस में बढ़ी सुरक्षा

अभिजीत दिपके के बाद नेहा बोरा को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, वह कनॉट प्लेस जाने की कोशिश कर रहे थे। दिपके के अलावा आइसा प्रमुख नेहा बोरा को भी दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में जाने के दौरान मंडी हाउस में हिरासत में ले लिया है। वह सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंडी हाउस में प्रदर्शन कर रही थीं। उनके अलावा आइसा के कई अन्य प्रदर्शनकारी भी हिरासत में लिए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने पहले अभिजीत दिपके से तिरंगा मार्च नहीं निकालने की गुजारिश की थी। इसके लिए पुलिस आज दिपके के दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी पहुंची थी और बिना अनुमति के मार्च नहीं निकालने को लेकर नोटिस दिया था।दिल्ली पुलिस की टीम दिपके के झंडेवालान वाले घर पर पहुंची थी। यह घर दिपके के दोस्त का है। पुलिस से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, 'लहरा दो तिरंगा' मार्च नहीं निकालने को लेकर नोटिस देने के लिए 15 से 20 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे थे। उनका कहना है कि सेंट्रल पार्क के आसपास ब्नहस्स की धारा 163 लगी हुई है।वहीं, सीजेपी के इस तिरंगा मार्च को लेकर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस लोगों से गुजारिश कर रही है कि लोग सेंट्रल पार्क न जाएं, क्योंकि वहां पर धारा 163 लगी हुई है।हालांकि इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग हाथों में



तिरंगा लिए सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहे हैं। इनर सर्कल में लोगों की भीड़ और बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस नजर आ रही है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और भीड़ में शामिल होकर इनर सर्कल से होते हुए सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहे हैं।

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को तिरंगे से नफरत है। उन्होंने कहा कि RSS ने अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया। अब देशवासियों को तिरंगा फहराने से रोक रहे हैं। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया। उन्होंने यह भी कहा कि धरना प्रदर्शन की वजह से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।

गिरफ्तारी के विरोध में 'लहरा दो तिरंगा'

सदस्यों आशुतोष रांका और सौरव दास को तिरंगा फहराने की वजह से जेल में डालने का आरोप लगाते हुए दिपके ने आज शुक्रवार शाम को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में लहरा दो तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है। उनके मार्च को देखते हुए नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने पार्क को आम लोगों को बंद कर दिया है।

शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ताकत से डर

कॉकरोच पार्टी का तिरंगा मार्च पुलिस ने रोका

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

नई दिल्ली। ॅकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में %लहरा दो तिरंगा% रैली बुलाई थी। हालांकि आसपास इलाके में धारा 163 लागू थी। जिसके चलते ष्टछ्बक्क फाउंडर अभिजीत दीपके को वहां जाने नहीं दिया गया।6 दिनों में दीपके को दूसरी बार कस्टडी में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहल दीपके को विमान से हिरासत में लिया गया था, अगले दिन छोड़ दिया गया।हिरासत में लिए जाने से पहले दीपके ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा- दिल्ली पुलिस से 7-8 पुलिसवाले आए। वे बोले कि आप लोगों



को भड़का रहे हैं। आप तिरंगा लहराने जा नहीं सकते। मतलब अपने ही देश में तिरंगा लहराने से मना किया जा रहा है।

ममता बनर्जी ने कहा कि अभिजीत दीपके को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हाथ में रखने के लिए हिरासत में लिया गया है। जरा सोचिए, स्वतंत्र भारत में हमारे युवाओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने पर हिरासत में लिया जा रहा है।यह किसी अघोषित आपातकाल से कम नहीं है। असहमति से डरने वाली सरकार अब पूरी पीढ़ी को चुप कराने के लिए डराने की कोशिश कर रही है।कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके को केवल इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वह राष्ट्रीय ध्वज लेकर निर्धारित स्थान की ओर जा रहे थे।कॉकरोच जनता पार्टी के अनुसार, यह कार्रवाई दिखाती है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ताकत से डर है।

ट्विशा सुसाइड केस में सास गिरबाला और पति समर्थ को SC का नोटिस, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर भी रोक

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में CBI, गिरबाला सिंह और समर्थ सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक भी लगाई।पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में ट्विशा शर्मा के पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ष्टछ्बक्क, गिरबाला सिंह और समर्थ सिंह को नोटिस भेजा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश भी दिया। याचिका में अपनी बेटी की मौत के मामले की सुनवाई को भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग है। याचिकाकर्ता नवनिधि शर्मा ने आशंका जताई है कि इस मामले में सबूतों को आरोपी ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह द्वारा प्रभावित किया जा सकता है।

620 फीट गहरे बोरवेल में फंसी मासूम की सांसें



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

फलोदी जिले की पुणियों की ढाणी में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है। स्ष्टक्रक्र, ह्वष्ठक्रक्र और पुलिस की टीमें संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जिला कलेक्टर, एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।राजस्थान के फलौदी जिले की लोहावट तहसील के नौसर ग्राम पंचायत क्षेत्र की पुणियों की ढाणी में एक बच्चा गहरे बोरवेल में गिर गया है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिएऔर पुलिस की टीमें संयुक्त टीम मौजूद है।

पंजाब की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा

अमित शाह का मान सरकार पर हमला, कहा- जवाब देना होगा

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

अमित शाह में दिरबा और मानसा की घटनाओं को लेकर पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार बनने पर पंजाब को नशामुक्त और गैंगस्टरमुक्त बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पंजाब में नशा, गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। उन्होंने भगवंत मान सरकार की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि पंजाब में नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, संगठित अपराध का खतरा बढ़ रहा है सवाल खड़े हो रहे हैं।



शाह ने सुरक्षित पंजाब बनाने का संकल्प दोहराया

अमित शाह ने कहा, 'मैं पंजाब की जनता के सामने अपना संकल्प दोहराता हूं कि हमारी सरकार बनने पर हम नशामुक्त, गैंगस्टरमुक्त और सुरक्षित पंजाब बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है- नशे के कारोबार पर प्रहार, युवाओं के भविष्य की रक्षा, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई और कानून का ऐसा राज, जिसमें कोई भी नागरिक भय के साये में जीने को मजबूर न हो।'

अमित शाह ने इन दो घटनाओं का जिक्र किया

पंजाब के मानसा जिले में 13 अक्टूबर को परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना उनके फेसबुक लाइव के दौरान कैमरे पर कैद हुई थी। वह मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा नशीली गोलियां बेचे पर सवाल कर रहे थे। इसी दौरान बहस बढ़ने पर आरोपी ने उन पर गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

न्यूज इन शॉर्ट

`मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान' से सोमारू राम को मिली नई जिंदगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता से एक बुजुर्ग के जीवन में छाई निराशा अब नई उम्मीद और उजाले में बदल गई है। तोकापाल विकासखंड की ग्राम पंचायत छापरभानपुरी के 68 वर्षीय सोमारू राम दोनों आंखों में मोतियाबिंद की वजह से पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुके थे। हालत यह थी कि वे बिना लाठी के एक कदम भी नहीं चल पाते थे और दैनिक आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहने को विवश थे। जिससे वे अत्यंत मानसिक तनाव और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे थे। उनकी इस लाचारी के बीच 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान' एक जीवनदायी वरदान साबित हुआ। अभियान के अंतर्गत यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छापर भानपुरी में पदस्थ ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट ऑफिसर सुदीप प्रमाणिक ने सोमारू राम की आंखों की गहन जांच की, जिसमें दोनों आंखों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम ने न केवल उन्हें ऑपरेशन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया, बल्कि आवश्यक परामर्श और रेफरल प्रक्रिया को सुगमता से पूरा कराते हुए उनका सफल ऑपरेशन भी सुनिश्चित किया। ऑपरेशन के उपरांत सोमारू राम की आंखों की रोशनी पूरी तरह लौट आई है और उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। अब उन्हें चलने के लिए किसी लाठी या सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे आत्मनिर्भर होकर अपने सारे काम स्वयं करने लगे हैं। जिस व्यक्ति को कभी लाचार समझकर उपेक्षित किया जाता था, आज वही सोमारू राम अपने हाथों से अपने और अपने परिवार के लिए घर का निर्माण कर रहे हैं तथा खेत के कार्यों में भी हाथ बंटा रहे हैं। इस अविश्वसनीय बदलाव पर भावुक होते हुए सोमारू राम ने कहा कि पहले उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और वे दूसरों पर आश्रित थे, लेकिन इस सफल उपचार ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी है, जिसके लिए वे स्वास्थ्य विभाग और शासन का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। यह प्रेरक मामला सिद्ध करता है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रियता और समय पर की गई स्क्रीनिंग ग्रामीण अंचलों में असहाय बुजुर्गों के जीवन में स्वाभिमान और नई ऊर्जा का संचार कर सकती है।

रसेवा संकल्प अभियान से ग्रामीण अंचलों तक पहुंच रही आयुष चिकित्सा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को आयुष चिकित्सा पद्धति से परामर्श और उपचार की सुविधा मिल रही है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के ग्राम धरमपुर में आयोजित शिविर में 57 मरीज लाभान्वित हुए।शिविर में ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया। साथ ही, आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आयुष चिकित्सा पद्धतियां स्वास्थ्य संवर्धन और रोगों की रोकथाम में सहायक हैं। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से इन पद्धतियों को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने और आमजन को सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

कौन्दकेरा-02 आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के रिक्त पद के लिए दावा-आपत्ति 26 अक्टूबर तक

गरियाबंद। एकीकृत बाल विकास परियोजना गरियाबंद अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति होने पर अभ्यर्थी 26 अक्टूबर 2026 तक पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना गरियाबंद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बारूला सेक्टर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कौन्दकेरा के कौन्दकेरा-02 आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका का एक पद रिक्त है। उक्त पद पर भर्ती के लिए 20 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की छानबीन के बाद अनंतिम सूची जारी की गई है। अनंतिम सूची के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के इच्छुक अभ्यर्थी ई-भर्ती पोर्टल ई-भर्ती पोर्टल पर जाकर 26 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

महतारी वंदन से आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ रहीं महिलाएं

अब वे स्वयं आय अर्जित कर रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे रही हैं

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल देने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। योजना के तहत हर माह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों और छोटे-मोटे खर्चों को स्वयं पूरा कर रही हैं। इससे परिवार की जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी बढ़ी है और आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है।

जशपुर जिला की कुनकुरी की महिलाओं ने बताया कि योजना की राशि प्रत्येक माह उनके बैंक खाते में जमा हो जाती है। इस नियमित सहायता से घरेलू आवश्यकताओं और व्यक्तिगत खर्चों के लिए उन्हें सहूलियत मिली है। अब



छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम हुई है और वे अपने खर्चों का बेहतर प्रबंधन कर पा रही हैं।श्रीमती ज्योति पांडेय ने बताया कि पहले उन्हें अपनी छोटी जरूरतों के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से अब वे अपने दैनिक खर्च स्वयं पूरा कर लेती हैं। इससे उन्हें आर्थिक आत्मविश्वास मिला है।श्रीमती रेहाना खातून के लिए योजना की सहायता स्वरोजगार की शुरुआत का आधार बनी। उन्होंने बताया कि पहले वे मजदूरी करती थीं। योजना से मिली राशि की मदद से उन्होंने घर पर छोटा व्यवसाय शुरू किया। अब वे स्वयं आय अर्जित कर रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे रही हैं।

श्रीमती कविता ने कहा कि योजना से मिलने वाली राशि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार है। वहीं श्रीमती अंजू ने बताया कि अब छोटे-मोटे खर्चों के लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। योजना ने उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आ रही ये कहानियां बताती हैं कि नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं के जीवन में किस तरह सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कुनकुरी की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना से उन्हें आर्थिक संबल मिला है। अब वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ परिवार की प्रगति में भी सहभागी बन रही हैं।

'किसानों की सुविधा सर्वोपरि, आगामी धान खरीदी के लिए समय रहते पूरी करें सभी तैयारियां: दयाल दास बघेल'

'कस्टम मिलिंग में तेजी लाने और धान के उठाव की व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर'

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा है कि आगामी धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को पंजीयन और टोकन प्राप्त करने से लेकर खरीदी केंद्र में धान विक्रय तक किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल, बिजली, पेयजल सहित किसानों की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खाद्य मंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों, कस्टम मिलिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न भंडारण एवं परिवहन सहित विभागीय योजनाओं



और गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी होनी चाहिए। खरीदी शुरू होने से पहले सभी केंद्रों में आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता का परीक्षण कर कमियों को दूर किया जाए।

'धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा का रखें विशेष ध्यान'

मंत्री श्री बघेल ने कहा कि खरीदी केंद्र तक पहुंचने वाले किसान को अनावश्यक प्रतीक्षा अथवा असुविधा का सामना न करना पड़े। टोकन व्यवस्था सुचारु रखी जाए और किसानों को प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए।

'प्रधानमंत्री आवास योजना से कविता बाई के पक्के घर का सपना हो रहा साकार'

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

हर परिवार का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी पक्की छत हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता सके। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तनोद निवासी श्रीमती कविता बाई के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण इसी सपने को साकार करने की उम्मीद लेकर आई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत उनके आवास को स्वीकृति मिलने से परिवार के लिए अपना पक्का घर बनाने की राह आसान हुई है।

कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों के लिए पक्का घर केवल चारदीवारी और छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार होता है। श्रीमती कविता बाई भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही आशियाना चाहती थीं, जहां उन्हें स्थायी आवास की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास की स्वीकृति मिलने से उनकी इस इच्छा को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है।

'अपने घर की उम्मीद को मिला नया सहारा'

श्रीमती कविता बाई के लिए आवास की स्वीकृति परिवार की एक बड़ी जरूरत पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पक्का घर बनने से परिवार को बेहतर रहन-सहन, सुरक्षा और दैनिक जीवन में सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। योजना से मिली सहायता ने उनके परिवार को अपने आवास के सपने के करीब पहुंचाया है।

'सेवा सेतु से आसान हुई प्रमाण पत्र की राह, रामप्रसाद को महज चार दिनों में मिला बच्चे का आय प्रमाण पत्र'

'पामगढ़ के सेवा सेतु केंद्र में किया आवेदन, समय पर प्रमाण पत्र मिलने से लंबी प्रतीक्षा से मिली राहत'

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

शासकीय सेवाएं जब सरल और समयबद्ध तरीके से नागरिकों तक पहुंचती हैं, तो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी आसान हो जाता है। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम कोसीर निवासी श्री रामप्रसाद के लिए सेवा सेतु केंद्र ऐसी ही सुविधाजनक व्यवस्था साबित हुआ है। अपने बच्चे का आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उन्होंने तहसील कार्यालय पामगढ़ स्थित सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया और महज चार दिनों में उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। समय पर आवश्यक दस्तावेज मिलने से उन्हें लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी।

श्री रामप्रसाद को अपने बच्चे के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए वे तहसील कार्यालय स्थित सेवा सेतु केंद्र पहुंचे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए चार दिनों के भीतर आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। प्रमाण पत्र शीघ्र मिलने से उनका काम आसानी से पूरा हो गया और उन्हें अनावश्यक प्रतीक्षा से राहत मिली।

'चार दिनों में प्रमाण पत्र मिलने से मिली राहत'

श्री रामप्रसाद के लिए सेवा सेतु केंद्र की यह सुविधा उपयोगी साबित हुई। तहसील स्तर पर ही आवेदन करने और निर्धारित समय में प्रमाण पत्र प्राप्त होने से उन्हें आवश्यक दस्तावेज हासिल करने में सहूलियत हुई। उन्होंने प्रमाण पत्र समय पर



मिलने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो रहा है। श्री रामप्रसाद ने इस सुविधाजनक व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

'नागरिकों के लिए सरल हो रही शासकीय सेवाओं की प्रक्रिया'

सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को आय, जाति, निवास सहित विभिन्न आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे नागरिकों को तहसील स्तर पर ही आवश्यक सेवाओं का लाभ मिल रहा है तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सहज और सुविधाजनक बन रही है।

सक्षम योजना से चंचल तिवारी बनीं आत्मनिर्भर, फैंसी स्टोर खोलकर अपनाया स्वरोजगार

सक्षम योजना से चंचल तिवारी बनीं आत्मनिर्भर, फैंसी स्टोर खोलकर अपनाया स्वरोजगार

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी कड़ी में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के छुईखदान नगर निवासी श्रीमती चंचल तिवारी ने छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाया है।

योजना के अंतर्गत उन्हें 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने अपना फैंसी स्टोर स्थापित कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है।



श्रीमती चंचल तिवारी ने योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता का सदुपयोग करते हुए फैंसी स्टोर का कारोबार शुरू किया। उनके स्टोर में महिलाओं के श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन एवं अन्य फैंसी सामग्रियां उपलब्ध हैं। इस व्यवसाय से उन्हें स्वयं की आय अर्जित करने का अवसर मिला है। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में भी सकारात्मक पहल हुई है।श्रीमती तिवारी के लिए सक्षम योजना अपने सपनों को साकार करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिली। आज वे अपने फैंसी स्टोर के माध्यम से स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उनका यह प्रयास अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। श्रीमती चंचल तिवारी ने सक्षम योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शासन की ऐसी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान करती हैं। सक्षम योजना जैसी पहल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है।

प्रशासनिक सुधारों को मिलेगी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पहचान

आईआईएम रायपुर में पंजीयन विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न

आईआईएम रायपुर में पंजीयन विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न, प्रशासनिक सुधारों को मिलेगी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पहचान

पंजीयन विभाग के नवाचारों, चुनौतियों और समाधान पर तैयार होंगी केस स्टडी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशन की पहल

संवाददाता ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक पहचान दिलाने की पहल की जा रही है। इसी उद्देश्य से नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर में पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय श्वर्कशॉप ऑन केस राइटिंग एंड कोलैबोरेटिव पब्लिकेशनश् 15 अक्टूबर को संपन्न हुई। 14 एवं 15 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यशाला में विभागीय सुधारों, महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों, उनके क्रियान्वयन में आई चुनौतियों तथा



अधिकारियों द्वारा विकसित व्यावहारिक समाधानों को केस स्टडी के रूप में तैयार कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित कराने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार एवं जनहितकारी पहल की गई हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक श्री पुष्पेंद्र मीणा के नेतृत्व में विभाग द्वारा पंजीयन सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन सुधारों के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों को अब व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत कर शोध, अध्ययन और प्रशासनिक प्रशिक्षण का हिस्सा बनाने की पहल की गई है।

'छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक नवाचारों से सीख सकेंगे देश-दुनिया के नीति-निर्माता'

कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य पंजीयन विभाग में हुए सुधारों को केवल प्रशासनिक उपलब्धियों तक सीमित न रखकर उन्हें अध्ययन और शोध के उपयोगी उदाहरणों के रूप में विकसित करना है। विभागीय सुधारों को लागू करते समय अधिकारियों के सामने अनेक व्यावहारिक चुनौतियां आईं, जिनका समाधान स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक अनुभवों और नवाचारों के माध्यम से किया गया। इन अनुभवों को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करने से देश-दुनिया के शिक्षाविदों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, प्रशासकों और नीति-निर्माताओं को छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से सीखने का अवसर मिलेगा।

यह पहल प्रशासनिक सुधारों के अनुभवों को संस्थागत ज्ञान में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे सफल कार्यप्रणालियों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और समस्याओं के व्यावहारिक समाधान को अन्य विभागों एवं संस्थानों के साथ साझा करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

'दो दिनों तक केस स्टडी लेखन, शोध और प्रकाशन की बारीकियों पर प्रशिक्षण'

कार्यशाला के प्रथम दिन विशेषज्ञों ने केस स्टडी लेखन की आवश्यकता, उसकी संरचना, उपयुक्त विषयों के चयन, समस्याओं की पहचान तथा प्रशासनिक अनुभवों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की तकनीकों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों को बताया गया कि विभागीय कामकाज के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, उनके पीछे की परिस्थितियां, क्रियान्वयन में आई कठिनाइयां और उनके समाधान किस प्रकार एक उपयोगी एवं प्रभावशाली केस स्टडी का आधार बन सकते हैं।

दूसरे दिन केस स्टडी तैयार करने की व्यावहारिक प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया। इसमें आवश्यक सूचनाओं का संकलन, तथ्यों का सत्यापन, संबंधित व्यक्तियों के साक्षात्कार, केस की रूपरेखा तैयार करने और विश्लेषणात्मक लेखन की विधियों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही टीचिंग नोट तैयार करने, उपयुक्त अकादमिक जर्नल एवं प्रकाशन मंच के चयन, समीक्षा तथा प्रकाशन की प्रक्रिया के संबंध में भी विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन प्रदान किया।

'आईआईएम रायपुर के विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव'

कार्यशाला में पंजीयन विभाग के डीआईजी श्री मदन लाल कोर्पे एवं डीआईजी श्रीमती उषा साहू सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर-इन-चार्ज प्रो. संजीव पाराशर, कार्यक्रम निदेशक प्रो. प्रणित कुमार रॉय, प्रो. सत्यसिबा दास, प्रो. मनोजीत चट्टोपाध्याय, अन्य विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रजनी को मिला संबल, नवजात के पोषण हेतु मिली आर्थिक सहायता

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक आधार बनकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और नवजात शिशु के पोषण में सहयोग दिया जा रहा है।

जिला मुख्यालय कोण्डागांव के तहसीलपारा वार्ड की निवासी श्रीमती रजनी ठाकुर को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता



प्राप्त हुई। प्रसव के बाद जब उन्हें बच्चे की फीडिंग के लिए पर्याप्त दूध नहीं आ रहा था, तब नवजात शिशु के पोषण की चिंता उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ऐसे कठिन समय में योजना के तहत प्राप्त राशि उनके लिए मददगार साबित हुई। इस राशि से उन्हें बच्चे के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक सहायता मिली।

श्रीमती रजनी ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद उसके समुचित पोषण की व्यवस्था करना उनके लिए महत्वपूर्ण था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मिली आर्थिक सहायता से उन्हें काफी राहत मिली। इस सहयोग ने बच्चे के पोषण की जरूरतों को पूरा करने में मदद की और कठिन समय में परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया।

जशपुर में लंबित पेंशन एवं वेतन निर्धारण प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित

सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में जशपुर जिले में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले में लंबे समय से लंबित वेतन निर्धारण एवं पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए आयोजित विशेष जिला स्तरीय शिविर में कुल 81 प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया। इनमें वेतन निर्धारण के 69 और पेंशन से संबंधित 12 प्रकरण शामिल हैं।



इस पहल से सेवानिवृत्त हो चुके तथा सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर संभाग सरगुजा के निर्देशानुसार 14 अक्टूबर को कलेक्टोरेट जशपुर के सभाकक्ष में विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अपने कार्यालयों से संबंधित लंबित वेतन निर्धारण एवं पेंशन प्रकरण प्रस्तुत किए। संभागीय अधिकारियों द्वारा इन प्रकरणों की दस्तावेजों सहित गहन जांच कर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए मौके पर ही निराकरण किया गया।

'लंबित प्रकरणों के समाधान से कर्मचारियों को मिली राहत'

जिला कोषालय अधिकारी श्री चन्द्रकांत ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं पेंशन संबंधी लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना था। विशेष रूप से ऐसे कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जशपुर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री साय के गृह जिले जशपुर के कुनकुरी तहसील अंतर्गत नारायणपुर स्थित कपरी नाला में 2 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र की लगभग 150 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम करने और कृषि गतिविधियों को अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।



कपरी नाला में निर्माणाधीन इस परियोजना का उद्देश्य वर्षा जल का संचयन कर उसका कृषि कार्यों में बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। क्षेत्र में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। स्टॉप डैम के निर्माण से वर्षा जल को रोककर उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकेगा। इससे किसानों को खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और फसलों के बेहतर उत्पादन की संभावनाएं मजबूत होंगी।

'150 हेक्टेयर कृषि भूमि होगी सिंचित, सिंचाई का प्रतिशत बढ़कर 37.91 तक पहुंचने की संभावना'

कपरी नाला में स्टॉप डैम के निर्माण से लगभग 150 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। विभागीय जानकारी के अनुसार, इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई का प्रतिशत बढ़कर 37.91 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद किसानों को आगामी कृषि सत्र 2027-28 से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है।सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को समय पर फसलों की सिंचाई करने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ाने, फसलअधिक लाभकारी बनाने के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

'जल संरक्षण के साथ भू-जल संवर्धन और ग्रामीण जनजीवन को मिलेगा लाभ'

कपरी नाला में स्टॉप डैम का निर्माण जल संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु के दौरान बहकर निकल जाने वाले पानी को रोककर उसका संचयन किया जा सकेगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलने और जल स्तर में सुधार होने की संभावना है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को निस्तारी संबंधी जरूरतों के लिए भी पानी की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी। जल संचयन की इस व्यवस्था से स्थानीय जल संसाधनों के संरक्षण और उनके समुचित उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने पर पेयजल स्रोतों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

नियद नेल्ला नार 2.0 : 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का दिया जा रहा है सीधा लाभ



मुख्य सचिव ने नियद-नेल्ला-नार और बस्तर मुन्ने 2.0 के कार्यों की समीक्षा की

मुख्य सचिव ने नियद-नेल्ला-नार और बस्तर मुन्ने 2.0 के कार्यों की समीक्षा की

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की महत्वकांक्षी कार्यक्रम नियद नेल्ला-नार योजना 2.0 और बस्तर मुन्ने 2.0 के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को सीधे 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कार्ययोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। नियद-नेल्ला-नार 2.0 के तहत दूरस्थ वनांचल और पूर्व नक्सल प्रभावित 10 जिला- बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कोण्डागांव, गरियाबंद, मोहला-मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और छुईखदान शामिल है। मुख्य सचिव ने 10 जिलों के दूरस्थ वनांचल एवं पूर्व नक्सल प्रभावित ग्रामों में रहने वाले परिवारों तक व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं जैसे- मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन-सक्रिय नल, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन-धन योजना शामिल है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट I योजना जैसी कुल 31 योजनाएं शामिल हैं।

जिला अस्पताल सूरजपुर में 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जटिल कूल्हे की सफल

जिला अस्पताल सूरजपुर में 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जटिल कूल्हे की सफल सर्जरी

स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से स्थानीय स्तर पर मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

जिला अस्पताल सूरजपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के समन्वित प्रयास से 73 वर्षीय महिला की जटिल कूल्हे की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह उपलब्धि जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और गंभीर मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओड़गी निवासी 73 वर्षीय श्रीमती राजकुमारी, बढ़ती उम्र के



कारण दोनों कूल्हों के खराब होने की समस्या से पीड़ित थीं। उपचार के लिए वे जिला अस्पताल सूरजपुर के हड्डी रोग विभाग पहुंचीं, जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय साहू द्वारा उनकी प्रारंभिक जाँच एवं एक्स-रे कराया गया। जाँच में दोनों कूल्हों के खराब होने की पुष्टि हुई। साथ ही, उनके शरीर में खून की कमी भी पाई गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने तथा उचित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के लिए तत्काल पहल की गयी। मरीज की स्थिति को देखते हुए उन्हें सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया। वार्ड के नर्सिंग स्टाफ ने चिकित्सकों के निर्देशानुसार उनका उपचार किया। स्वास्थ्य में सुधार होने तथा ऑपरेशन के लिए उपयुक्त स्थिति बनने के बाद निश्चेतना विभाग द्वारा आवश्यक जांच की गई और सर्जरी की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि पर ऑपरेशन की आवश्यक तैयारियां पूरी की गईं। डॉ. अजय साहू ने बताया कि यह मामला काफी जटिल था, लेकिन पूरी टीम के समन्वय एवं सहयोग से सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न की जा सकी। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर 2026 को भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन के सहयोग से सूरजपुर निवासी 60 वर्षीय श्री राजकुमार का सफल ऑपरेशन किया गया था।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह ने कहा कि कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशानुसार जिला अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को भी बेहतर उपचार मिल सके और उन्हें इलाज के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। हमारा प्रयास है क्मिर उपलब्ध कराई जा सकें।

अवैध रेत परिवहन पर सख्त कार्रवाई, बेमेतरा में 6 हाइवा वाहन जब्त

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सतत निगरानी

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई के तहत बेमेतरा जिले में खनिज विभाग ने रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 6 हाइवा वाहनों को जब्त किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के नियमानुसार उपयोग, राजस्व हितों के संरक्षण तथा अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा



खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम के लिए निगरानी और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

बेमेतरा कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने 14 एवं 15 अक्टूबर 2026 को ग्राम कठिया-राका और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 6 हाइवा वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों को सुरक्षार्थ संबंधित थाने की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग द्वारा संबंधित वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने कहा

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने सड़कों की मरम्मत और बीटी पैच कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने कोरबा जिले में निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने कोरबा में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने और उनकी कड़ी व नियमित



निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोरबा के कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी इस दौरान मौजूद थे।श्री बंसल ने अधिकारियों को सड़कों के बीटी पैच मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल-पुलियों की मरम्मत प्राथमिकता से आवागमन की सुविधा मिल सके।

इन कार्यों का किया निरीक्षण

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने कोरबा जिले में कटघोरा-हरदीबाजार-बलौदा-अकलतरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक मार्ग तक निर्माणाधीन सीमेंट-कांक्रीट सड़क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 2.84 किलोमीटर लंबे इस सड़क के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को इसे शीघ्र पूर्ण करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री आर.के. रात्रे, अधीक्षण अभियंता (वि/या) श्री सुरेश भूपल और कोरबा संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री जी.आर. जांगड़े सहित विभागीय अनुविभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

सेवा संकल्प अभियान के तहत 'आसरा' एवं 'करुणा' अभियान से जुड़ी जन-जागरूकता गतिविधियां

बेसहारा बच्चों और असहाय वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण, विधिक सहायता एवं सम्मानजनक जीवन के लिए किया जागरूक

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित 'आसरा' एवं 'करुणा' अभियान के तहत जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बेसहारा तथा होटल और सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें संरक्षण, विधिक सहायता एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना और असहाय वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करना था।

कार्यक्रम में बच्चों एवं युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। उन्हें नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित नागरिकों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा सखी वन स्टॉप सेंटर 181 की सेवाओं के बारे में भी बताया गया।

नागरिकों को जानकारी दी गई कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 संकटग्रस्त एवं जरूरतमंद बच्चों को सहायता और संरक्षण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं, सखी वन स्टॉप सेंटर 181 हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता, परामर्श और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है।

कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों से जरूरतमंद बच्चों एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता रखने, उनके अधिकारों का सम्मान करने और संकट की स्थिति में संबंधित विभागों तथा सहायता सेवाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की गई। साथ ही, कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को विधिक सहायता और उपलब्ध संरक्षण सेवाओं से जोड़कर उनका सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की केसवर्कर सुश्री स्तुति राजवाड़े, जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता श्री कृष्णा कुमार चंद्राकर एवं आउटरीच वर्कर श्री महेश पटेल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।

न्यूज इन शॉर्ट

कृषक उन्नति योजना से शंकर प्रसाद की खेती को मिलेगा आर्थिक संबल

रायगढ़। जिले में डिजिटल माध्यमों से शासकीय सेवाओं की उपलब्धता ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक बन रही है। छत्तीसगढ़ शासन का 'सेवा सेतु पोर्टल' नागरिकों को आवश्यक शासकीय दस्तावेज उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो रहा है। इससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत कम होने के साथ ही समय और धन की भी बचत हो रही है। खरसिया तहसील के ग्राम टुसेकेला निवासी देवेन्द्र यादव को भी इस सुविधा का लाभ मिला है।देवेन्द्र यादव को शैक्षणिक कार्यों, छात्रवृत्ति और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए आय एवं निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने खरसिया तहसील कार्यालय स्थित सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के बाद मात्र चार से पांच दिनों में उनका निवास प्रमाण पत्र और 8 अक्टूबर 2026 को जारी हो गया। दोनों आवश्यक दस्तावेज मिलने से उन्हें अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिली।शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया सुगम होने के साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में भी सुविधा मिल रही है। देवेन्द्र यादव ने प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जरूरी दस्तावेज प्राप्त करना आसान हुआ है। इससे उनके समय और आर्थिक संसाधनों की बचत हुई है।

35 टन माल की हेराफेरी का खुलासा, रायपुर से फरार ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार

. दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में माल परिवहन के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब भेजने के लिए सौंपे गए 35.222 टन ष्ठह्लष्ट साल बीज खली को निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचाने के मामले में फरार ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को 15 अक्टूबर 2026 को रायपुर के टाटीबंध इलाके से पकड़ा गया। मामले में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ट्रक और पूरा माल पहले ही बरामद कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग की अदालत में न्यायिक रिमांड के लिए पेश किया गया है। वहीं, फरार ट्रक चालक जयप्रकाश की तलाश जारी है।

मनोरमा इंडस्टरीज, करंजा भिलाई के मैनेजर मनोज कुमार सिंह ने चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 22 नवंबर 2025 को कंपनी ने यूटीएस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से 35.222 टन ष्ठह्लष्ट साल बीज खली पंजाब के भटिंडा भेजने का सौदा किया था। माल परिवहन के लिए ट्रक क्रमांक स्क्क16 ॥ 5792 तय किया गया था। परिवहन का कुल किराया 1 लाख 39 हजार 471 रुपये निर्धारित हुआ था। समझौते के अनुसार, ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे को 1 लाख 9 हजार 471 रुपये अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया था। इसके बावजूद कंपनी का माल निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचा।प्रार्थी मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे, ट्रक मालिक रोहित उर्फ राहुल दीक्षित और चालक जयप्रकाश को माल परिवहन से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोप है कि निर्धारित किराया तय होने और अग्रिम भुगतान मिलने के बावजूद माल भटिंडा स्थित गंतव्य तक नहीं पहुंचाया गया। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 289/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने ट्रक मालिक रोहित उर्फ राहुल दीक्षित से घटना में इस्तेमाल ट्रक क्रमांक स्क्क16 ॥ 5792 बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने परिवहन के लिए सौंपे गए 35.222 टन ष्ठह्लष्ट साल बीज खली को भी जब्त कर लिया। वाहन और माल की बरामदगी के बाद पुलिस ने प्रकरण से जुड़े अन्य व्यक्तियों की तलाश तेज की। इस दौरान ट्रांसपोर्टर अवनीश दुबे फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी पतासाजी कर रही थी। इसी बीच आरोपी के रायपुर में मौजूद होने की जानकारी मिलने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत पिपरिया शा.उ.मा. विद्यालय में हुआ जागरूकता कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता में छात्राओं ने रखे सशक्त विचार

शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति बालिकाओं को किया जागरूक, विजेता छात्राओं को मिले पुरस्कार





एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरिया में जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब), महिला एवं बाल विकास विभाग, एमसीबी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम की थीम 'बेटियां ही भविष्य हैं'

कार्यक्रम में छात्राओं को बालिका शिक्षा के महत्व, लैंगिक समानता, बाल विवाह की रोकथाम, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि बालिकाओं को शिक्षा और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराकर ही समाज को सशक्त और प्रगतिशील बनाया जा सकता है। छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।

भाषण प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिए प्रेरक संदेश

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान 'बेटियां ही भविष्य हैं' विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बालिकाओं ने बेटी शिक्षा, समान अवसर, महिला सुरक्षा और बालिका सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं ने समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी

कार्यक्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में भी जानकारी दी गई। गर्भवती महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने और संबंधित सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया गया। कार्यक्रम में महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर अपराध संबंधी हेल्पलाइन 1930 तथा हेल्पलाइन नंबर 1515 के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्य सुष्मिता सालोमान, वरिष्ठ शिक्षक डॉ. विनोद पाण्डेय, जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र से सुश्री शैलजा गुप्ता (जेंडर विशेषज्ञ), श्रीमती अनीता कुमारी शाह (वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ), सखी वन स्टॉप सेंटर से पूजा रजक (केस वर्कर), सुप्रिया तिवारी (पैरा मेडिकल) तथा विधिक सेवा प्राधिकरण से श्रीमती अंजनी यादव (अधिकार मित्र) सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।

24 बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ली पार्टी की सदस्यता

जनकपुर में वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जनकपुर द्वारा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन के दौरान ÷वोट चोर गद्दी छोड़÷ के नारे लगाए गए।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक गुलाब कमरो, सांसद प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अंकुर सिंह, अवधेश सिंह, रामनरेश पटेल,अमोल सिंह,संजीव गुप्ता,देवेंद्र पांडेय,देवेंद्र सिंह,लाल साय बैगा ,धर्मेंद्र शर्मा,रामू सिंह,जयमुनिया बैगा,कमल जोगी,आशु,नूर मोहम्मद, संजय,सौरव सिंह,शामिल अहमद ,रामनारायण बैगा ,शाहबाज खान,शिवम पयाशी सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों और मताधिकार की सुरक्षा पर जोर दिया।

24 बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ग्रहण की कांग्रेस की सदस्यता

विरोध प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी सामने आया। कार्यक्रम में बजरंग दल के 24 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नए सदस्यों का स्वागत किया।कांग्रेस नेताओं ने संगठन को मजबूत करने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही। जनकपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया, वहीं 24 नए सदस्यों के पार्टी में शामिल होने से संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा मिली।



कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के सभी विभागों का किया औचक निरीक्षण

ऑफलाइन कार्य बंद कर ऑनलाइन फाइल संधारण के दिए निर्देश



स्थापना, खनिज, जनसंपर्क, महिला एवं बाल विकास, आबकारी, खाद्य सहित विभिन्न विभागों का लिया जायजा, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में संचालित सभी विभागों का औचक निरीक्षण कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं एवं विभागीय कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थापना शाखा, खनिज विभाग, जनसंपर्क विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आबकारी विभाग, विपणन शाखा, खाद्य विभाग, उद्योग विभाग सहित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कार्यालयीन कार्यों की स्थिति का अवलोकन करते हुए सभी विभागों को ऑफलाइन कार्यप्रणाली बंद कर शासकीय फाइलों का संचालन एवं संधारण ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुशासन एवं समयबद्धता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

ऑफलाइन कार्य बंद कर सभी फाइलों का ऑनलाइन संधारण सुनिश्चित करें

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुश्री जांगड़े ने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि कार्यालयीन कार्यों में ऑफलाइन प्रक्रिया को बंद कर सभी शासकीय फाइलों एवं अभिलेखों का संधारण ऑनलाइन माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में डिजिटल प्रणाली को प्राथमिकता देते हुए फाइलों का संचालन, संधारण एवं निराकरण ऑनलाइन सुनिश्चित किया जाए। इससे शासकीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइलों की निगरानी आसान होगी तथा प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोई भी फाइल अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और सभी विभाग ऑनलाइन फाइल प्रबंधन व्यवस्था का गंभीरता से पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और जवाबदेह बनेगी।

कार्यालयीन अनुशासन और समयबद्ध कार्य निष्पादन पर विशेष जोर

कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में पहुंचकर कार्यालयीन व्यवस्थाओं, शासकीय अभिलेखों के संधारण तथा विभागीय कार्यों के संचालन की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालयों में अनुशासन एवं कार्यकुशलता बनाए रखना प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी है। सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा में कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें तथा कार्यालयीन कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

मनेन्द्रगढ़ में इलेक्ट्रिकल दुकान का शटर तोड़कर तांबे के तार चोरी, एक आरोपी गिरफ्तार

दो किलो तांबे का तार बरामद, तीन अन्य आरोपी फरार; चोरी के दौरान निगरानी कर रहा था गिरफ्तार आरोपी

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

मनेन्द्रगढ़ में आत्मानंद स्कूल के पास स्थित इलेक्ट्रिकल दुकान का शटर तोड़कर तांबे के तार और नकदी चोरी करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करीब दो किलो तांबे का तार बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग तीन हजार रुपये बताई गई है।



मामले में तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

दुकान से एक क्विंटल तार और नकदी गायब:पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नई सब्जी मंडी मनेन्द्रगढ़ निवासी धरमू राजभर ने 10 अक्टूबर 2026 को सिटी कोतवाली में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के भतीजे संदीप राजभर की किरोड़ीमल पेट्रोल पंप के बगल में एस.आर. इलेक्ट्रिकल नाम से दुकान है, जहां मोटर वाइंडिंग और बिजली उपकरणों की मरम्मत का काम किया जाता है।शिकायतकर्ता की तबीयत खराब होने के कारण वह 6 अक्टूबर से उपचार कराने रायपुर गया हुआ था। इस दौरान 8 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे दुकान बंद कर घर जाने के बाद 9 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे पड़ोसी ने फोन कर दुकान में चोरी होने की जानकारी दी।

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने सौंपा प्रमाण पत्र, त्वरित सेवा से अनावश्यक भागदौड़ और समय की हुई बचत

सेवा सेतु ऐप से संदीप यादव को दूसरे ही दिन मिला निवास प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन से आसान हुई प्रक्रिया

एक सत बुलेटिन ➤ रायपुर

शासकीय सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सरल, सुलभ और समयबद्ध बनाने की पहल नागरिकों के लिए सुविधाजनक साबित हो रही है। जांजगीर-चांपा जिले के चांपा निवासी श्री संदीप यादव को सेवा सेतु ऐप के माध्यम से आवेदन करने के दूसरे ही दिन निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया। ऑनलाइन आवेदन और त्वरित निराकरण से श्री संदीप यादव को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और अनावश्यक भागदौड़ से भी राहत मिली।

श्री संदीप यादव को अपने आवश्यक कार्य के लिए निवास प्रमाण पत्र की जरूरत थी। उन्होंने सेवा सेतु ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार त्वरित कार्रवाई की गई और अगले ही दिन उनका निवास प्रमाण पत्र तैयार हो गया। कम समय में प्रमाण पत्र उपलब्ध होने से उनका जरूरी काम आसानी से पूरा हो सका।



ऑनलाइन आवेदन किया और अगले ही दिन मिल गया प्रमाण पत्र

श्री संदीप यादव ने सेवा सेतु ऐप की सुविधा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था से प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। पहले आवश्यक दस्तावेजों के लिए कार्यालयों में जाने और समय लगने की चिंता रहती थी, लेकिन अब डिजिटल माध्यम से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आवेदन के दूसरे ही दिन निवास प्रमाण पत्र मिलना उनके लिए सुखद अनुभव रहा।

श्री संदीप यादव ने इस नागरिक हितैषी डिजिटल सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु ऐप आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने की सराहनीय पहल है।

डिजिटल सेवाओं से आसान हो रही नागरिकों की राह

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासकीय सेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेवा सेतु ऐप इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से नागरिक आवश्यक प्रमाण पत्रों और अन्य शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे आवेदन की प्रक्रिया सरल होने के साथ सेवाओं के समयबद्ध निराकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्री संदीप यादव की यह 'सेवा की कहानी' डिजिटल शासन व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

न्यूजीलैंड टेस्ट से पहले सीनियर खिलाड़ियों को रणजी खेलना होगा



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बीसीसीआई सीनियर भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए कह सकता है। खिलाड़ियों से कम से कम एक प्रथम श्रेणी मैच खेलने की उम्मीद की जा रही है।कप्तान शुभमन गिल पंजाब और उप-कप्तान केएल राहुल कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी में खेल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह भी रेड-बॉल मैच में नजर आ सकते हैं।द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों के वर्कलोड और टीम की क्लीयरेंस के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। हाल में चोट से लौटे आकाश दीप और नितीश कुमार रेड्डी पर भी चयनकर्ताओं की नजर रहेगी।बुमराह के लिए लचीला रुख

बुमराह के वर्कलोड को देखते हुए बीसीसीआई उन्हें रणजी ट्रॉफी या इंडिया-ए के लिए प्रथम श्रेणी मैच खेलने का विकल्प दे सकता है। यानी उनके लिए घरेलू मैच का फॉर्मेट और संख्या फिटनेस के हिसाब से तय की जा सकती है।

फैसला 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के अनुभव के बाद आया है। उस सीरीज में भारत को 0-3 से हार मिली थी। बोर्ड इस बार न्यूजीलैंड दौरे से पहले खिलाड़ियों को पर्याप्त रेड-बॉल मैच प्रैक्टिस देना चाहता है।

19 नवंबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज

भारत को न्यूजीलैंड में 19 नवंबर से दो टेस्ट की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अहम होगी। टीम के हालिया टेस्ट प्रदर्शन को देखते हुए नए सत्र में बेहतर तैयारी पर जोर दिया जा रहा है।

आखिरी टी20 के लिए टीम इंडिया ने बदला स्क्वॉड, भुवनेश्वर कुमार की हुई एंट्री



वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी खेमे में बड़ा बदलाव हुआ है. बाएं हाथ के अहम तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के गेंदबाजी वाले कंधे में चोट लग गई है. जिसके चलते भारतीय पुरुष सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने अनुभवी स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को बेंगलुरु में होने वाले आखिरी टी20 मैच के लिए नेशनल स्क्वॉड में शामिल कर लिया है. सीरीज फिलहाल 2-2 की रोमांचक बराबरी पर खड़ी है।

सिर्फ 133 रन और वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर स्मृति मंधाना, रचेंगी वो इतिहास जो पुरुष क्रिकेट में भी नहीं हुआ



एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज यानी 16 अक्टूबर से जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज के साथ भारतीय क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत होगी. स्मृति मंधाना पहली बार बतौर फुल टाइम कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरेंगी.भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज यानी 16 अक्टूबर से जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज के साथ भारतीय क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत होगी. स्मृति मंधाना पहली बार बतौर फुल टाइम कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरेंगी.इस सीरीज के दौरान स्मृति मंधाना के पास क्रिकेट के इतिहास का वो सबसे बड़ा मील का पत्थर हासिल करने का मौका होगा, जिसे आज तक पुरुष या महिला कैटेगरी में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज छू नहीं सका है.

इस सीरीज के दौरान स्मृति मंधाना के पास क्रिकेट के इतिहास का वो सबसे बड़ा मील का पत्थर हासिल करने का मौका होगा, जिसे आज तक पुरुष या महिला कैटेगरी में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज छू नहीं सका है. 2 / 5

मंधाना टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनने से सिर्फ 133 रन दूर हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक का फायदा मिला; गिल पहले, रोहित चौथे नंबर पर

कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की पारी खेली थी। इस पारी में पहली बार उन्होंने 9 छक्के लगाए थे। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की पारी खेली थी। इस पारी में पहली बार उन्होंने 9 छक्के लगाए थे।वराट कोहली ट्टष्ट की वनडे बैटर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 139 रन की पारी खेलने का उन्हें फायदा मिला।कोहली के अब 796 रेटिंग पॉइंट हैं। वे टॉप पर मौजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल से सिर्फ 20 पॉइंट पीछे हैं। रैंकिंग हर हफ्ते बुधवार को जारी की जाती है।27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाए थे।



यह उनका वनडे करियर का 55वां शतक था। इसी पारी के दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन भी पूरे किए। वह सचिन तेंदुलकर के बाद यह आंकड़ा छूने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। भारत ने मुकाबला 8 विकेट से जीता था।

टॉप-4 में 3 भारतीय बैटर्स

बैटर्स रैंकिंग के टॉप-4 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। शुभमन गिल ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाया था। उन्होंने 110 रन की पारी खेली। इसके बाद गिल 816 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर-1 पर हैं। कोहली दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

कोहली ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पीछे छोड़। वे 794 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत के रोहित शर्मा 753 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर हैं।

व्यापार

भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की दूरी

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन विदेशी निवेशकों का भरोसा उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो साल में करीब 40 अरब डॉलर की विदेशी पूंजी बाहर निकल चुकी है। बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, अब सिर्फ मजबूत ग्रोथ विदेशी निवेशकों को भारत की ओर खींचने के लिए काफी नहीं है।भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन इसका असर विदेशी निवेशकों के रुख पर उसी तरह नहीं दिख रहा। देश की जीडीपी ग्रोथ मजबूत होने के बावजूद विदेशी



संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में पहले की तरह पैसा नहीं लगा रहे हैं। पिछले दो साल में भारतीय शेयरों से करीब 40 अरब डॉलर (?3।84 लाख करोड़) की विदेशी पूंजी बाहर निकल चुकी है।

ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन रिसर्च की 21 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले कुछ पुराने संकेत अब पहले जितने असरदार नहीं रह गए हैं।

सोना आज 712 और चांदी 673 महंगी

लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद रिकवरी; 10 ग्राम गोल्ड 1.48 लाख पारंग

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

सोने-चांदी की कीमतों में आज लगातार दो दिन की गिरावट के बाद तेजी है। इंडिया बुलियन एंड वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 712 रुपए बढ़कर 1,48,379 रुपए पर आ गया।इससे पहले 29 सितंबर को यह 1,47,667 रुपए पर था। वहीं, एक किलो चांदी 673 रुपए बढ़कर 2,22,273 रुपए पर आ गई है, जो मंगलवार को 2,21,600 रुपए पर थी।ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी-एक शहर से दूसरे शहर सोना ले जाने में ईंधन और सुरक्षा खर्च जुड़ता है, जिससे दूरी बढ़ने पर दाम बढ़ते हैं।

खरीदारी की मात्रा- दक्षिण भारत में यादा खपत (करीब 40त्न) के कारण वेलर्स बड़ी खरीद करते हैं, लेकिन छूट का फायदा सीमित रहता है।



लोकल वेलरी एसोसिएशन- राय और शहर के वेलरी एसोसिएशन स्थानीय मांग-सप्लाई के आधार पर रेट तय करते हैं।

पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य- वेलर्स का खरीदी रेट तय करता है कि वे ग्राहकों को कितनी कीमत में बेचेंगे।

सोना इस साल 15,180 महंगा और चांदी 8,147 गिरी

इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 15,180 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं, चांदी 8,147 रुपए सस्ती हुई है। 31 दिसंबर 2025 को 10द्द सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.48 लाख रुपए पर पहुंच गया है।

वहीं, चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.22 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑलटाइम हाई भी बनाया था।

:एपल पे भारत में लॉन्च, एक्सिस बैंक पहला पार्टनर बना; जानें- कैसे काम करेगा

आईफोन-एपल वॉच से बिना पिन-ओटीपी पेमेंट कर सकेंगे

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

एपल ने भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एपल पे को लॉन्च कर दिया है। साथ ही आईफोन और एपल वॉच यूजर्स के लिए कार्डलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का नया ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है। इसके जरिए यूजर्स बिना पिन-ओटीपी पेमेंट कर सकेंगे।

एपल की इस सर्विस के लिए एक्सिस बैंक पहला पार्टनर बना है। शुरुआत में इसके तहत एक्सिस बैंक के वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट दिया जा रहा है।कंपनी के मुताबिक, एपल पे के जरिए यूजर्स अपने एलिजिबल क्रेडिट कार्ड्स को एपल वॉलेट एप में जोड़कर खरीदारी कर सकेंगे।

भारत में शुरुआती फेज में यह सर्विस हजारों मर्चेंट्स पर अवेलेबल होगी। आने वाले समय में अन्य बैंकों, नेटवर्क और मर्चेंट एप्स को भी इससे जोड़ा जाएगा।



एक्सिस बैंक कार्ड को एपल वॉलेट से कैसे जोड़ें?

एक्सिस बैंक के एलिजिबल वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड होल्डर अपने कार्ड को एपल वॉलेट में आसानी से जोड़ सकते हैं। कार्ड जोड़ने के लिए यूजर्स एक्सिस बैंक एप के लेटेस्ट वर्जन या आईफोन में पहले से मौजूद वॉलेट एप का सहारा ले सकते हैं।

वॉलेट एप में कार्ड जोड़ने के लिए एप खोलकर प्लस साइन पर टैप और स्क्रीन पर दिख रहे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके बाद एपल पे सपोर्ट करने वाले मर्चेंट्स पर आसानी से पेमेंट किया जा सकेगा।

खास बात यह है कि एपल पे का यूज करने पर भी यूजर्स को उनके कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स और अन्य बेनिफिट्स पहले की तरह ही मिलते रहेंगे।

कैसे काम करता है और कौन इस्तेमाल कर सकता है?

अभी एप्पल पे की सुविधा सिर्फ एक्सिस बैंक के वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ग्राहक अपने इन कार्ड को एप्पल पे में जोड़ सकते हैं। इसके बाद वे भारत में हजारों दुकानों, ऑनलाइन दुकानों और उन सभी जगहों पर भुगतान कर सकते हैं, जहां एनएफसी से भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल पे और एप्पल वॉलेट की उपाध्यक्ष जेनिफर बेली ने भारत में एप्पल पे की शुरुआत को देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अहम कदम बताया।

चैरिटी कमिश्नर तक पहुंची नोएल टाटा की शिकायत

एजेंसी ➤ नई दिल्ली

नोएल टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई, टाटा समूह की प्रमुख परोपकारी संस्थाओं टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन हैं। नोएल टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई, टाटा समूह की प्रमुख परोपकारी संस्थाओं टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन हैं।टाटा ग्रुप में लीडरशिप और गवर्नेंस को लेकर विवाद बढ़ गया है। टाटा ट्रस्ट्स के जॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन ने सवाल उठाया कि नोएल टाटा चेयरमैन बने रहने के साथ-साथ ग्रुप की मुख्य ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी टाटा संस के मामलों में कैसे शामिल हो सकते हैं।

इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, श्रीनिवासन ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर नोएल को हमेशा के लिए ट्रस्टी और चेयरमैन बनाए रखने पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा, उन्होंने नोएल के बेटे नेविल टाटा को ट्रस्टी बनाए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं।

श्रीनिवासन के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स अब समाजसेवा के अपने मुख्य काम से भटककर कंपनियों के बिजनेस फैसलों में दखल दे रहा है। ट्रस्टी खुद बड़े कारोबारी सौदों को तय करने, बातचीत करने और उन्हें फाइनल कराने में लगे हैं, जो कि चैरिटी ट्रस्ट के नियमों के खिलाफ है।

टाटा और श्रीनिवासन के बीच विवाद की 2 वजह

1. टाटा संस को शेयर बाजार में उतारा जाए या नहीं, इस पर दोनों के विचार अलग हैं। श्रीनिवासन चाहते हैं कि कंपनी बाजार में लिस्ट हो, जबकि नोएल टाटा इसके सख्त खिलाफ हैं।2. टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और उनके काम करने के तौर-तरीकों को लेकर भी दोनों के बीच मतभेद हैं।

विवाद इतना गहरा गया कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने वेणु श्रीनिवासन को टाटा संस की बोर्ड बैठकों में हिस्सा लेने और वोट डालने से रोकने का प्रयास किया।



मंत्री मारे थप्पड़

यह लोकतंत्र है या कोई गुंडा-मवाली राज है? क्या कोई मंत्री, जनता के बीच, शिकायतों के माहौल में, किसी युवक को सरेआम थप्पड़ मार सकता है? क्या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता मंत्री के सामने, मंत्री के परिवार को, गालियां देने का दुस्साहस कर सकता है? दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने आवेश में आकर एक युवक को थप्पड़ मारा है। यह संज्ञेय और दंडनीय अपराध है, लेकिन चौतरफा राजनीतिक दबाव के बाद पुलिस ने शिकायत तो दर्ज की है, लेकिन वह 'गैर-संज्ञेय अपराध सूचना' (एनसीआर) ही है, जो महज खानापूर्ति है। आम आदमी पार्टी (आप) के जिस विधायक जरनैल सिंह ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की परतें उखाड़ कर मंत्री जी के सामने सब कुछ बेपरदा कर दिया था, उनके खिलाफ भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मंत्री ने विधायक पर ही 50 लाख रुपए की 'कमीशन' मांगने का आरोप चस्पां कर दिया है और विभाग के इंजीनियर से पुलिस में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। वह प्राथमिकी है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। मंत्री प्रवेश वर्मा की सफाई है कि जब इंजीनियर और ठेकेदार ने 'घूस' देने से साफ इंकार कर दिया, तो 'आप' विधायक ने सड़क उखाड़ कर साबित करने की कोशिश की कि देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता 'खस्ताहाल' है। मंत्री जी! आप झूठ बयां कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मॉनसून की बारिश सारी पोल खोल देती है। सड़कों की गुणवत्ता ही 'खस्ताहाल' नहीं है, बल्कि गहरे, खुले गड्ढे भी हैं, जो 'मौत के कुएं' साबित हो रहे हैं। और फिर विधायक जरनैल सिंह ने अपने हाथों से सड़क के टुकड़े उखाड़ कर मंत्री के सामने रखे थे,उन पर संबद्ध अधिकारियों और ठेकेदार को तलब क्यों नहीं किया गया? इंजीनियर को तुरंत निलंबित क्यों नहीं किया गया? विधायक ने तो काले, कुरूप सच को नंगा कर दिया था। क्या दिल्ली सरकार ऐसे ठेकेदारों को भी संरक्षण दे रही है?

(एक नजर)

10 दिन बाद नक्षत्र बदलेंगे शनि!

वैदिक योतिष में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना गया है. शनि ग्रह जब भी अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर काफी गहरा और दीर्घकालिक होता है. योतिषीय गणनाओं के अनुसार, साल 2026 में 9 अक्टूबर 2026 को शनि देव का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन उत्तर भाद्रपद शनि देव का अपना ही नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इस नक्षत्र में शनि का प्रवेश अत्यंत प्रभावशाली और फलदायी साबित होगा. शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं. ऐसे में जब शनि का नक्षत्र गोचर होता है, तो वर्षों से अटके काम गति पकड़ने लगते हैं. शनि के इस महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन का असर यूं तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि 9 अक्टूबर के इस नक्षत्र गोचर से किन राशियों को करियर, बिजनेस और धन के मामले में जबरदस्त सफलता मिलने वाली हैवृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिनके साथ शनि देव का मित्रवत संबंध है. 9 अक्टूबर के बाद आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और बड़े पद का लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे।

विचार

शक्ति संतुलन, कूटनीति और जलवायु संकट

विकेश कुमार बडोला

लेखक

जब तक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों- अमरीका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के देशज हित सधते रहे, तब तक महासभा का आयोजन शेष विश्व के लिए एक साधारण आयोजन हुआ करता था। किंतु जब से उक्त पांच देशों के मध्य स्वार्थ साधने एवं शीर्ष पर स्थापित होने की स्पर्धा बढ़ी तथा इनके प्रतिस्पर्द्धी बनकर दुनिया के कुछ अन्य देश भी खड़े हुए हैं, तब से महासभा की वार्षिक बैठक आरोप-प्रत्यारोप का मंच बन गई है। पांच देशों के प्रतिस्पर्द्धी बनकर खड़े होने वाले देशों में सम्मिलित हैं भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया।

प्रत्येक वर्ष किसी न किसी ऋतु में कोई न कोई प्रतिकूल संकटजन्य ऋतुगत घटना हो ही रही है। इस सत्य को सम्मुख रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और विशेषकर विकसित सदस्य देशों को जीवन-जगत के संबंध में मानवीय एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण अंगीकार करना होगाविश्व में अनेक स्तर पर हो रहे युद्धों, दो या अधिक देशों के पारस्परिक सशस्त्र संघर्षों तथा अन्य राजनीतिक प्रतिकूलताओं व नकारात्मक प्रतिस्पर्द्धाओं के बीच संपन्न संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक महासभा में अत्यधिक हलचल रही। सन् 2014 के बाद महासभा में ऐसी हलचल प्रत्येक वर्ष हो रही है और आगामी वर्ष में तीव्र से तीव्रतम हो रही है। जब तक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों- अमरीका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के देशज हित सधते रहे, तब तक महासभा का आयोजन शेष विश्व के लिए एक साधारण आयोजन हुआ करता था। किंतु जब से उक्त पांच देशों के मध्य स्वार्थ साधने एवं शीर्ष पर स्थापित होने की स्पर्धा बढ़ी तथा इनके प्रतिस्पर्द्धी बनकर दुनिया के कुछ अन्य देश भी खड़े हुए हैं, तब से महासभा की वार्षिक बैठक आरोप-प्रत्यारोप का मंच बन गई है। पांच देशों के प्रतिस्पर्द्धी बनकर खड़े होने वाले देशों में सम्मिलित हैं भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। विशेषकर भारत में 2014 के बाद जो शासन तंत्र स्थापित हुआ और जिस प्रकार स्वदेशी गौरव के प्रति एक तीव्र शासकीय एवं लोकतांत्रिक हलचल होनी आरंभ हुई, उस परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र के प्रभुत्व में दबदबा बनाए रखने वाले प्रमुख पांच देशों में से अमरीका, चीन एवं ब्रिटेन को कुछ अधिक बेचैनी हो गई है। भारत, रूस एवं चीन के नेतृत्व में ब्रिक्स सहित दक्षिण एशियाई एवं मध्य पूर्वी देशों के बीच अमरीकी-यूरोपीय शासकीय प्रभुत्व को खंडित करने के लिए वैचारिक एवं व्यावहारिक स्तर पर



जो नवचेतना जागृत हुई है, उसने भी विश्व को पिछले एक-डेढ़ दशक में पहले तो शीतयुद्ध में धकेला और अब उस कारण धीरे-धीरे विभिन्न स्तरों पर देशों के मध्य सशस्त्र संघर्ष भी बढ़ रहा है।जिस प्रकार विश्व समय-समय पर शीतयुद्ध से प्रभावित रहा है, उसी प्रकार भारत के केंद्रीय कल्याणकारी भूमिका में अवतरित होने के बाद संपूर्ण विश्व में शीत-समन्वय की धारणा जड़ें जमा रही है। अघोषित रूप से भारत की विदेश नीति सर्वमान्य हो रही है। विदेशों में भारत के मानवतावादी सिद्धांत की प्रशंसा हो रही है। किसी भी मंच पर भारत का मत स्वार्थ से विलग जगहित के लिए होता है। इस भाव को दुनिया के अधिसंख्य देश पहचान रहे हैं। भारत के शत्रु देश भी इस भावना से भलीभांति परिचित हैं। इसीलिए वे भारतीय पराभव के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त हैं। महासभा के मंच पर जहां अधिसंख्य देशों एवं उनके प्रमुखों तथा प्रमुखों की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधियों ने अपने-अपने हितों के रक्षार्थ भाषण किया तथा अपने शत्रु देश के प्रति आक्रोश से भरकर अपनी-अपनी आपत्तियां प्रकट कीं, वहीं भारतीय प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अत्यंत शांत होकर, संयम एवं विनीत भावना के साथ वैश्विक युद्धजन्य संघर्षों, प्राकृतिक चुनौतियों, असमान सुख-सुविधाओं के वितरण, आदि मानवीयता-केंद्रित विषयों पर संभाषण किया तथा पारस्परिक सेवा व सहयोग के विचार के साथ विकसित होने के विचार पर बल दिया। हालांकि उन्होंने भी भारत के पारंपरिक शत्रु देश पाकिस्तान पर मंच से दोषारोपण किया, किंतु ऐसा आरोप कल्पना आधारित नहीं है। यह अनेक स्तर पर प्रामाणिक है। यह अलग बात है कि न तो अमरीका और न ही संयुक्त राष्ट्र ने इस पर आज तक गंभीरतापूर्वक विचार किया है।

विचार

पारदर्शिता की राह में स्वायत्तता का सवाल

डा. सतपाल

लेखक

इस विधेयक के तहत राय के अंतर्गत छह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार का हालिया फैसला केवल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का विषय नहीं है, बल्कि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही के बीच संतुलन का भी प्रश्न है। सरकार का तर्क है कि सरकारी धन से चलने वाले विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह होनी चाहिए।

सवाल यह नहीं होना चाहिए कि लोक सेवा आयोग अच्छा है या विश्वविद्यालय की चयन समिति। असली सवाल यह होना चाहिए कि हिमाचल को सबसे योग्य शिक्षक किस व्यवस्था से मिलेंगे और उस व्यवस्था में पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित होगीहिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश राय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 को विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित कर दिया है। इसकी वास्तविक प्रभावशीलता अब माननीय रायपाल महोदय की स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगी। इस विधेयक के तहत राय के अंतर्गत छह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार का हालिया फैसला केवल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का विषय नहीं है, बल्कि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही के बीच संतुलन का भी प्रश्न है। सरकार का तर्क है कि सरकारी धन से चलने वाले विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह होनी चाहिए। दूसरी ओर, विश्वविद्यालयों के भीतर यह चिंता स्वाभाविक है कि यदि शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया सरकारी भर्ती व्यवस्था के अधीन कर दी जाती है, तो इससे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। क्या पारदर्शिता और स्वायत्तता एक-दूसरे की विरोधी हैं, या दोनों को साथ लेकर चलने वाली कोई बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है।यही इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विधानमंडल के अधिनियम के तहत हुई। यह प्रदेश का सबसे पुराना प्रमुख बहुविषयक विश्वविद्यालय है। इसके बाद राय की विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप कई विशिष्ट विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में, नौणी में डा. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की 1985 में, हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की 2010 में, नेरचौक में अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की 2018 में तथा मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में हुई। स्पष्ट है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी विशिष्ट शैक्षणिक भूमिका और आवश्यकताएं हैं। ऐसे में सभी के लिए



एक समान भर्ती व्यवस्था लागू करना कितना उचित होगा, यह विचारणीय प्रश्न है। प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों की व्यवस्था पहले से मौजूद है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार भी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विषय विशेषज्ञों और शैक्षणिक प्रतिनिधियों वाली चयन समितियों की व्यवस्था की गई है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि विश्वविद्यालयों में अब तक नियुक्तियां किसी नियम-कायदे के बिना होती रही हैं। विश्वविद्यालयों के पास अपनी वैधानिक चयन व्यवस्था रही है और नियुक्तियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं तथा चयन प्रक्रिया का पालन किया जाना अपेक्षित रहा है। अन्य विश्वविद्यालय की तरह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अपनी भर्ती शाखा और चयन प्रक्रिया भी लंबे समय से अस्तित्व में रही है। यह भी विचारणीय है कि प्रदेश विश्विद्यालयों की शिक्षक भर्तियों के साथ-साथ राय आयोग की भर्तियां भी कटघरे में रही हैं। वर्तमान में शायद इस फैसले की पृष्ठभूमि में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्तियों से जुड़ी आपत्तियां भी महत्वपूर्ण हैं।वर्ष 2020 से 2023 के बीच हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियां हुईं जिन्हें महालेखा परीक्षक ने शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के पर्याप्त सत्यापन अभिलेख उपलब्ध न होने पर सवाल उठाए तथा कुछ मामलों में पात्रता संबंधी अनियमितताएं भी चिन्हित कीं। लेकिन महालेखा परीक्षक ने नियुक्तियों को अवैध घोषित नहीं किया अपितु रिपोर्ट का मुख्य जोर प्रक्रिया, अभिलेखों और प्रमाणपत्रों के सत्यापन की कमी पर था। इसलिए इस रिपोर्ट को आधार बनाकर विश्वविद्यालय की प्रत्येक नियुक्ति पर प्रश्नचिह्न लगाना न तो उचित होगा और न ही तथ्यपरक। यदि किसी नियुक्ति प्रक्रिया में प्रमाणपत्रों का विधिवत सत्यापन नहीं हुआ, चयन प्रक्रिया के अभिलेख पूरे नहीं हैं या पात्रता की जांच में कमी रह गई है, तो व्यवस्था को सुधारना आवश्यक है। सरकारी धन से चलने वाले किसी भी संस्थान में नियुक्ति प्रक्रिया इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बाद में किसी को उस पर उंगली उठाने का अवसर ही न मिले। विश्वविद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति सामान्य सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति से अलग होती है। किसी प्रशासनिक पद के लिए सामान्य परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया पर्याप्त हो सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय में शिक्षक केवल एक कर्मचारी नहीं होता। वह अध्यापन, अनुसंधान, मार्गदर्शन और अकादमिक नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए किसी शिक्षक का चयन केवल सामान्य भर्ती प्रक्रिया से नहीं, बल्कि उसके विषय ज्ञान, शोध कार्य, प्रकाशनों, अध्यापन क्षमता और संबंधित वाले विशेषज्ञों द्वारा होना चाहिए।

विचार

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मिलावटखोरी रोकने की व्यवस्था

उमेश चतुर्वेदी

लेखक

महाराष्ट्र की घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां तेज-तर्रार अधिकारी खाद्य प्रशासन को मिला है। दूसरे इलाकों में ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में मिलावटखोरी बंद हो गई है। इससे शायद ही किसी को इनकार हो कि शुद्ध खाना और दवा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है। बिडंबना ही कहेंगे कि जिस मिलावटखोरी से हर साल देश में करीब दो लाख लोग मौत की भेंट चढ़ जाते हैं, फिर भी हमारी कानूनी तंत्र इस पर प्रभावी रोक लगाने में नाकाम रहा है। वैसे तो हर साल त्योहारी सीजन के साथ ही मिलावटखोरी की चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन इन दिनों इस चर्चा की वजह महाराष्ट्र के तेजतर्रार आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे की कार्रवाई है। मुंढे ने जब से महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए के आयुक्त का पद संभाला है, मिलावटखोरों की शामत आ गई है। उन्होंने खाद्य कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। महाराष्ट्र एफडीए की टीमों ने शुरुआती 100 दिनों में ही 904 से यादा छापे मारकर 450 से अधिक मिलावटखोरों को गिरफ्तार किया और करोड़ों के



मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए। इस कार्रवाई से महाराष्ट्र में डिटर्जेंट और रसायनों से बने नकली दूध और ताड़ के तेल से बनने वाले एनालॉग पनीर का रैकेट ध्वस्त हो गया है। नियमों और स्वच्छता मानकों की अनदेखी करने वाले कई नामी फूड चेन्स, बड़े रेस्तराओं आदि के लाइसेंस तक निलंबित या रद्द किए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र की घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां तेज-तर्रार अधिकारी खाद्य प्रशासन को मिला है। दूसरे इलाकों में ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में मिलावटखोरी बंद हो गई है। इससे शायद ही किसी को इनकार हो कि शुद्ध खाना और दवा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है। ब्रिटेन और अमेरिका में ध्यान रखा जाता है कि उपभोक्ताओं तक वही सामान पहुंचे, जो शुद्ध है। ऐसी व्यवस्था भारत में भी की गई है। 2006 में संसद से पारित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई का गठन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत कार्यरत इस संस्था का दायित्व खाद्य पदार्थों के मानकों पर निगाह रखना और उन्हें तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। रायों की पुलिस, प्रशासन और आपूर्ति अधिकारियों को भी अधिकार है कि वे मिलावटखोरी रोकें। त्योहारी सीजन में ये संस्थाएं कार्रवाइयां करती भी हैं।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 से हर साल करीब एक लाख से अधिक खाद्य नमूनों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर करीब आठ हजार से यादा खाद्य व्यावसायिक लाइसेंस रद्द भी किए गए हैं। लेकिन देश में इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया जा सका है। रोक ना लग पाने के पीछे मोटे तौर पर तीन कारण नजर आते हैं। पहला है, मुनाफाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति, दूसरा नैतिकता का क्षरण और तीसरा कारण निश्चित तौर पर प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार है।विनोबा भावे ने करीब आठ दशक पहले लिखे अपने निबंध 'नवयुवकों से दो बातें' में कहा है कि देश में सुराख ही सुराख हैं। उन्होंने राष्ट्ररूपी घड़े में बने इन सुराखों को सदाचार से भरने की अपील की है। कुछ उसी तरह व्यवस्था में अब भी सुराख हैं। हमारे तंत्र के बड़े हिस्से से सदाचार और कर्तव्यपराणयता गायब है। वह राष्ट्र निर्माण के भाव से दूर है। इस वजह से वक्त पर कार्रवाई नहीं होती। कई बार तंत्र को जानकारी होती है कि फलां कारोबारी आटे में पत्थर का सफेद बुरादा मिला रहा है, चावलों में प्लास्टिक के दाने फेंट रहा है, दवाओं के सैंपल में गड़बड़ी कर रहा है, नकली मावे की मिठाई बेच रहा है, जाली शराब बिक रही है। वक्त पर इन गड़बड़ियों की जानकारी होने के बावजूद मुनाफाखोर से मिलने वाली चंद रकम के एवज में वह चुप रह जाता है। भले ही नकली दूध पीने से नागरिक बीमार हो रहा हो या नकली शराब से निर्दोष जान जा रही हो। नैतिकता का क्षरण भी मिलावटखोरी के लिए जिम्मेदार है। नैतिकता की कमी मुनाफाखोर कारोबारी और उत्पादक के साथ तंत्र में भी पैठी हुई है।सत्ता संभालते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने तंत्र को चेताया था कि सब चलता है-वाली मानसिकता की अब गुंजाइश नहीं रही। शुरू में इससे ग्रस्त लोगों में भय दिखा, लेकिन अब तंत्र का बड़ा हिस्सा उसी पुराने ढर्रे पर चलता दिखता है, इसलिए मुनाफाखोरों और मिलावटखोरों का डर कम हो चला है। स्वास्थ्य संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस मामले में केंद्र के साथ राय सरकारों को भी कार्रवाई का अधिकार है। ऐसे में तंत्र को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए केंद्र और रायों की सरकारों को जीरो टालरेंस की नीति अख्तियार करना जरूरी लगता है। तभी मुनाफाखोर, मिलावटखोर और लापरवाह प्रशासनिक तंत्र के पेंच कसे जा सकते हैं।

इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य है कि खाद्यान्न में यह वृद्धि से अधिक रही है जो कि संतोषजनक स्थिति है और अभी तो भोजन पेट भर मिल रहा है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या 2025 में हमें पेट भर भोजन प्राप्त होगा? अगर नहीं तो हम आगे क्या करेंगे?

टिकाऊ खेती आज की आवश्यकता







जनसंख्या एवं खाद्यान्न उत्पादन

भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.7 करोड़ को छू चुकी है जो 1991-2000 तक 1.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि में रही, जबकि खाद्यान्न उत्पादन 2003-04 में 213.5 मिलियन टन तक पहुंचा अर्थात् 2.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से.

इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से तात्पर्य है कि खाद्यान्न में यह वृद्धि से अधिक रही है जो कि संतोषजनक स्थिति है और अभी तो भोजन पेट भर मिल रहा है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या 2025 में हमें पेट भर भोजन प्राप्त होगा? अगर नहीं तो हम आगे क्या करेंगे?

हमें आगे भी 21वीं सदी के बाद से खाद्यान्न में लगभग 25-30 प्रतिशत की वृद्धि कायम रखनी होगी अन्यथा पूरा देश हमारा सूखा घोषित हो जायेगा जिससे की लगभग 14 प्रतिशत उत्पादन में गिरावट होगी जो भविष्य के लिए प्रगति के उत्तम संकेत नहीं हैं.

भूमि-जल पर्यावरण

खेती में उर्वरकों, कीटनाशकों शाकनाशियों अर्थात् रसायनों के अत्यधिक प्रयोग में भूमि की दशा निश्चय ही खराब हुई है. जिससे की भूमि के लाभदायक कीट, केंचुए, जीवाणु इत्यादि नष्ट हुए हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म तत्वों में भी भारी कमी हुई. अतः जीवांश खादों के प्रयोग से हम रोक सकते हैं फसल चक्र अपना सकते हैं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कर सकते हैं कई जंगल भी नष्ट किये गये सघन पद्धतियों के प्रयोग के कारण जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है अर्थात् इसका दोहन कम किया जाए एवं इन्हें संरक्षित किया जाने का प्रयास करना नितांत आवश्यक है.

लाभ/खर्च अनुपात

हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की उपलब्धि बनाये रखने के लिए सस्य रसायनों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है. जिससे की हमारी भूमि में मृदा में तथा मृदा के गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है. यदि यह प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलती रही तो भूमि एवं जल की उपादेयता समाप्त हो जायेगी और नई पीढ़ी का जीवन ही असुरक्षित हो जायेगा वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र बराबर कम होता जा रहा है. ऐसी परिस्थिति में हम टिकाऊ खेती का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है तथा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि वर्तमान व भविष्य दोनों में संतुलन हो. इस प्रकार की खेती का प्रयोग करके हम अपने भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित तो कर रही है बल्कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं सुरक्षा करके या उन्हें सुरक्षित बनाये रखने का कर्त्तव्य भी पूरी तरह निभा रहे हैं. अर्थात् हमें टिकाऊ खेती का प्रयोग किया जाना चाहिए. जिसके द्वारा हमें आर्थिक लाभ एवं भारत सरकार को पूर्णतः उत्पादन से लाभ प्राप्त हो सके.

कृषि क्षेत्र में सम्पन्नता लाने के लिए उत्पादकता टिकाऊपन तथा समानता की बहुत जरूरत है हमें भारत में भी बदलते पर्यावरण में कृषि निर्वाह की प्राथमिकता देनी अनिवार्य आवश्यकता है. इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में हम आर्थिक दृष्टि से कारगर, पर्यावरण की दृष्टि त्रुटीहीन सामयिक दृष्टि से सुसंगत प्रौद्योगिकी जो कम लागत पर अधिक से अधिक कृषि उत्पाद दे सकें.

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टिकाऊ खेती मानव जाति को निरंतर खुशहाली प्रदान का वचन देती है.

टिकाऊ खेती का महत्व

टिकाऊ खेती का महत्व सबसे अधिक वर्तमान खेती की प्रणालियों, तरीकों एवं समस्याओं को सुधारने में है. टिकाऊ खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं मृदा, जल, ऊर्जा, वन-विकास एवं जंगली पशुओं की सुरक्षा या इन्हें सुरक्षित रखने से है. टिकाऊ खेती में इनके प्रबंधन पर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता है. कई प्रकार की उत्पन्न समस्याओं जैसे- सौर ऊर्जा का उचित प्रयोग, वातावरण प्रदूषण की रोकथाम पर्यावरण का संतुलन डगमगाना इत्यादि समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना ही इसमें निम्न विषय है अर्थात् भविष्य में टिकाऊ खेती के माध्यम से इन समस्याओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है.

टिकाऊ खेती का लाभः

- पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाये रखने में टिकाऊ खेती का प्रमुख कार्य है.
- वातावरणीय प्रदूषण कम होता है.
- लगाई फसलों की उत्पादन लागत कम आती है.
- प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उचित प्रकार से करते हैं.

धनिया की उन्नत खेती

धनिया हमारे दैनिक उपयोग के मसालों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो पूरे वर्ष सम्पूर्ण देश में उगाया जाता है इसलिए पूरे वर्ष आय का साधन हो सकता है, हरी पत्तियां सब्जियों में उपयोग की जाती हैं। धनिया में मधुर सुगंध कोरोमिन्डाल, लिनाकोल, एल्कोहल पदार्थ उपस्थिति के कारण होता है। सूखे धनिया के बीजों को रबी में बोया जाता है। मध्यप्रदेश का 70 प्रतिशत धनिया गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, दतिया जिले में उगाया जाता है इसके अलावा शाजापुर, मंदसौर, राजगढ़ जिलों में भी बोया जाता है। अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण उपज के लिये उन्नत तकनीक अपनाना आवश्यक है।





भूमि

असिंचित धनिया के लिये काली मिट्टी जिसकी जलधारण क्षमता एवं जल निकास वाली अच्छी भूमि हो और सिंचित धनिया बोने के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है जिसमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त हो।

खेत की तैयारी

असिंचित क्षेत्र में अंतिम वर्षा जल की नमी को संरक्षित करते हुए 2-3 जुताई कर यथाशीघ्र बुवाई करें तथा सिंचित खेत में खरीफ फसल की कटाई के बाद 2-3 जुताई करें।

बुवाई का समय

रबी में बुवाई के लिये 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक उपयुक्त समय है। देरी बुवाई करने पर भभूतिया रोग की संभावना बढ़ जाती है।

उन्नत जातियां

साधना,पंत हरितिमा, गुजरात धनिया, सिंधु,स्वाति, उदयपुर धनियां-20

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन

खेत की तैयारी के समय 15-20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद खेत में मिला दें। सिंचित अवस्था में प्रति हेक्टर 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 किलोग्राम पोटाश पर्याप्त होता है। जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा आधार खाद के रूप में बुवाई के समय बीज के नीचे ऊर कर दें तथा शेष नत्रजन की मात्रा प्रथम एवं द्वितीय सिंचाई के समय दें उस समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है।

बीज की मात्रा एवं बुवाई विधि

सिंचित अवस्था में बीज दर 12-15 किलो ग्राम तथा असिंचित अवस्था में 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। जिसे बुवाई पूर्व बीज को 24 घंटे पानी में भिगो कर रखें जिससे अंकुरण शीघ्र और अच्छा होता है। इसके बाद थाइरम या डाइथेम -एम 45 की 3 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज उपचारित कर बोयें। बुवाई कतारों में की जाती है जिसमें कतार से कतार की दूरी 25-30 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 5-7 सेमी रखें और बीज को 3-5 सेमी गहराई पर बुवाई करें।

निंदाई एवं गुड़ाई

धनिये की फसल में प्रथम निराई गुड़ाई बुवाई के 25-30 दिन पर करना चाहिये जिसमें जहां अधिक पौधे उगे हों वहां से पौधे उखाड़ दें।

सिंचाई

अच्छी पैदावार के लिये फसल की क्रान्तिक अवस्थायें - जैसे शाखायें फूटते समय, फूल आते समय, बीज बनते समय खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। सिंचाई 10-15 दिन के अंतराल पर करें जो मिट्टी की किस्म और मौसम पर निर्भर करता है।

फसल उत्पादन

धनिया की फसल बीज के लिये 140-150 दिन में तैयार हो जाती है। बीज के रूप में 15 से 20 क्विं. प्रति हेक्टर उत्पादन प्राप्त होता है। पत्तियों के रूप में बोने के 45 दिन पश्चात से पत्तियों की कटाई कर विक्रय किया जा सकता है।

धनिया कटाई के बाद प्रबंधन

- फसल अवधि पूर्ण होने के पश्चात जब दाने परिपक्व हो जाये एवं दाने हरे रहें तब उसे काटकर छायादार स्थान में सुखाना चाहिए। दाने हरे रंग के रहने से बाजार में अधिक कीमत मिलती



न्यूज इन शॉर्ट



पत्नी संग तीर्थराज पुष्कर पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल, भगवान ब्रह्मा के किए दर्शन

राजस्थान/रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल राजस्थान प्रवास के दौरान अपनी धर्मपत्नी के साथ तीर्थराज पुष्कर पहुंचे। यहां उन्होंने पवित्र पुष्कर सरोवर में विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद जगतपिता भगवान ब्रह्मा और मां सावित्री के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का यह दौरा धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा रहा। पुष्कर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूजा-अर्चना कर भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त की।राजस्थान प्रवास के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी धर्मपत्नी के साथ तीर्थराज पुष्कर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने सबसे पहले पवित्र पुष्कर सरोवर में पूजन कर धार्मिक परंपराओं का पालन किया। पुष्कर सरोवर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। यहां देशभर से श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। सांसद अग्रवाल ने भी अपनी पत्नी के साथ सरोवर पूजन कर अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त की। पुष्कर सरोवर में पूजन के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल जगतपिता भगवान ब्रह्मा के मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर भगवान ब्रह्मा के प्रसिद्ध मंदिर के कारण देशभर में विशेष धार्मिक पहचान रखता है। यह मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पुष्कर का संबंध भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है।भगवान ब्रह्मा के दर्शन के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मां सावित्री के दर्शन किए। मां सावित्री का मंदिर पुष्कर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। सांसद अग्रवाल ने अपनी पत्नी के साथ मां सावित्री के चरणों में श्रद्धा व्यक्त करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया।

महिला क्रेता को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, बचत की राशि से पूरी करेंगी घरेलू जरूरतें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को सरल, सुगम और किफायती बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सूरजपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की गृहिणी सुनीता के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराना अब पहले से अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीला हो गया है। महिला क्रेता के रूप में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें 3,940 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक बचत हुई। वहीं रजिस्ट्री के साथ स्वत: नामांतरण की सुविधा से उन्हें अलग से आवेदन करने और राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आर्थिक राहत के साथ समय की बचत ने उनके लिए संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सहज बना दिया।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल और मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, रजिस्ट्री के साथ स्वत: नामांतरण और डिजिटल सेवाओं का विस्तार इन सुधारों में प्रमुख हैं। इन व्यवस्थाओं का लाभ हितग्राहियों तक किस प्रकार पहुंच रहा है, यह जानने के लिए विभाग द्वारा सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव संकलित किए जा रहे हैं।सेवा संकल्प अभियान के तहत अपना अनुभव साझा करते हुए सुनीता ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के दौरान उन्हें महिला क्रेता के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिला।

18 लाख की चिरौंजी का अवैध परिवहन पकड़ाया, 12 क्विंटल माल जब्त

सब हेडलाइन: छिलके की आड़ में छुपाकर ले जा रहे थे चिरौंजी, मंडी अमले ने 55125 का जुर्माना वसूला

एक सत बुलेटिन ➤ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

कृषि उपज मंडी समिति पेंड्रा के अधिकारियों ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 लाख रुपए कीमत की चिरौंजी के अवैध परिवहन को पकड़ा है। मंडी अधिकारियों को मल्टीपरपज ग्राउंड पेंड्रा के पास वाहन क्रमांक छत्त10 ⁄ह 2133 (माजदा) खड़ा मिला। पूछताछ में ड्राइवर अनिल कुमार ने बताया कि वाहन में 130 बोरी चिरौंजी का छिलका लोड है जो सूर्या ट्रेडिंग कंपनी, गौरेला के मालिक सुबोध जैन पिता ज्ञानचंद जैन का है और बिलासपुर ले जाया जा रहा है।



संदेह होने पर अधिकारियों ने वाहन को मंडी परिसर लाकर अनलोड कराया। जांच में पाया गया कि 130 बोरी छिलके के नीचे 21 बोरी शुद्ध चिरौंजी छुपाकर रखी गई थी। प्रत्येक बोरी 60 किलो की थी, इस प्रकार कुल 12 क्विंटल 60 किलो चिरौंजी बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए है। ड्राइवर कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

अवैध परिवहन मानते हुए मंडी अधिनियम के तहत मंडी कर का 5 गुना जुर्माना सहित कुल 55,125 रुपए टैक्स वसूला गया। बताया गया कि उक्त फर्म द्वारा पिछले 30 वर्षों से चिरौंजी का व्यवसाय किया जा रहा है और न के बराबर मंडी टैक्स पटाया जा रहा है।

ट्रांसपोर्टर की भूमिका संदिग्ध

वाहन छत्त10⁄ह 2133 नायडू ट्रांसपोर्ट बिलासपुर का है। आरोप है कि इसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से बिना दस्तावेज के माल पेंड्रारोड से बिलासपुर और वहां से रेलवे की लीज बोगियों में दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में भेजा जाता है।

पत्रकार से मारपीट का मामला भी

गौरतलब है कि पूर्व में नई दुनिया के पत्रकार विपिन जैन ने ही सूर्या ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत मंडी अधिकारियों से की थी। शिकायत के बाद सुबोध जैन, ललित जैन, सुकांत जैन व उनके परिजनों द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी एफआईआर गौरेला थाने में दर्ज है।

पेंड्रा। मंडी समिति पेंड्रा ने 18 लाख की चिरौंजी का अवैध परिवहन पकड़ा। वाहन छत्त10⁄ह 2133 में 130 बोरी छिलके के नीचे 21 बोरी (12.60 क्विंटल) चिरौंजी छुपाकर बिलासपुर ले जाई जा रही थी। माल सूर्या ट्रेडिंग कंपनी गौरेला का है। वैध कागजात न मिलने पर 55125 रु जुर्माना वसूला गया। वाहन नायडू ट्रांसपोर्ट का है, जो रेलवे लीज से माल महानगरों में भेजता है।

सेवा संकल्प अभियान से सामने आई रामबती की सफलता की कहानी,

जल जीवन मिशन से घर तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल

'हर घर नल से जल' योजना से बदला जीवन, पानी के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से मिली राहत

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलावों की सफलता की कहानियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करीं के ग्राम जवारीटोला निवासी रामबती के जीवन में जल जीवन मिशन के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन आया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत संचालित जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर नल से जल' योजना से घर तक पेयजल की सुविधा मिलने से उनके दैनिक जीवन में सहूलियत बढ़ी है।

पानी के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से मिली राहत

रामबती बताती हैं कि पहले उन्हें स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल के लिए कुएं और हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। इसके लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी रोजमर्रा के घरेलू कार्यों के बीच पानी की व्यवस्था करना भी चुनौतीपूर्ण रहता था। अब घर पर ही नल से पेयजल उपलब्ध होने से उन्हें इस परेशानी से राहत मिली है। पानी लाने में लगने वाला समय बचने से दैनिक कार्यों को पूरा करना पहले की तुलना में आसान हुआ है।

जल जीवन मिशन से ग्रामीण जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

'हर घर नल से जल' योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की सुविधा पहुंचाना है। ग्राम जवारीटोला में इस पहल से रामबती जैसे ग्रामीणों को घर पर ही पानी की सुविधा मिलने से राहत मिल रही है। पेयजल की सुलभ उपलब्धता से घरेलू कार्यों को आसान बनाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

घर तक नल से पेयजल की सुविधा मिलने पर रामबती ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ÷यह योजना हमारे गांव और हमारे भविष्य को नई दिशा दे रही है।÷ घर पर पेयजल उपलब्ध होने से दैनिक जीवन की परेशानियां कम हुई हैं और परिवार को बड़ी राहत मिली है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सामने आई रामबती की यह सफलता की कहानी दर्शाती है कि जल जीवन मिशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण परिवारों के जीवन में सुविधा और सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक बन रही हैं। घर-घर तक पेयजल पहुंचाने की पहल ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के साथ बेहतर जीवन की उम्मीद को भी मजबूत कर रही है।

स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया

62 वर्ष की उम्र में फोर्स एकेडमी की कोच सुनीता सिंह ने जीता स्वर्ण पदक, छत्तीसगढ़ को किया गौरवान्वित

एक सत बुलेटिन ➤ मझगवां

प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प के सामने उम्र कभी बाधा नहीं बनती। इस बात को साबित करते हुए फोर्स एकेडमी मझगवां, जी.पी.एम. की कोच सुनीता सिंह ने 62 वर्ष की उम्र में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि से पूरे फोर्स एकेडमी परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है।कोयंबटूर, तमिलनाडु के नेहरू स्टेडियम में 7 से 11 अक्टूबर 2026 तक आयोजित



5वीं वेटरंस स्पोर्ट्स एंड गेम्स नेशनल चैंपियनशिप 2026 में कोच सुनीता सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। उनकी यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि खेल के प्रति समर्पण, नियमित अभ्यास, आत्मविश्वास और मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

प्रतियोगिता से वापस लौटने पर फोर्स एकेडमी मझगवां में कोच सुनीता सिंह का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर एकेडमी के समन्वयक लालजी पड़वार, मुख्य कोच पंचलाल लहरे (पूर्व आर्मी) कोच बलदाऊ, कोच गुमान सिंह, कोच रवि सिंह, कोच वसीम खान, कवर्धा सहित एकेडमी के प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। खिलाड़ियों ने अपनी कोच की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उनका आशीर्वाद लिया।

छह ट्रैक्टर और दो टिपर वाहनों को जब्त किया

अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग का शिकंजा, मनेंद्रगढ़ में दबिश देकर 6 ट्रैक्टर और 2 टिपर जब्त

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

जिले में खनिज संसाधनों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने और खनिज नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निगरानी बढ़ा दी गई है। कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में आज जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे छह ट्रैक्टर और दो टिपर वाहनों को जब्त किया।

विभिन्न क्षेत्रों में जांच के दौरान पकड़े गए वाहन

खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल ने तहसील मनेंद्रगढ़ के सिरौली, चैनपुर, हस्तिनापुर और घुटरा क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। इस दौरान रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त पाए गए छह ट्रैक्टर एवं दो टिपर वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद सभी वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्ट्रेट परिसर में रखा गया है। विभाग की इस पहल का उद्देश्य खनिजों के अनधिकृत परिवहन पर रोक लगाना और शासन के निर्धारित नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।



खनिज नियमों के उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई

खनिज विभाग के अनुसार, जब्त किए गए वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से जांच की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विश्व हाथ धुलाई दिवस पर विद्यार्थियों को दिया स्वच्छता और स्वस्थ जीवन का संदेश

ग्राम पंचायत चैनपुर के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, बच्चों को बताए हाथ धोने के सही तरीके और स्वच्छता के लाभ

एक सत बुलेटिन ➤ एमसीबी

विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर जिले के ग्राम पंचायत चैनपुर स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में 'स्वच्छ हाथ, स्वास्थ्य जीवन' की थीम पर हाथ धुलाई जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित हाथ धुलाई तथा संक्रामक बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि स्वच्छ हाथ न केवल अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, बल्कि अनेक बीमारियों से बचाव का प्रभावी माध्यम भी हैं।

हाथों की स्वच्छता से संक्रमण और बीमारियों से बचाव

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को गंदे हाथों के माध्यम से फैलने वाले बैक्टीरिया, वायरस एवं अन्य हानिकारक कीटाणुओं के संबंध में जानकारी दी गई। बच्चों को समझाया गया कि हाथों की नियमित सफाई नहीं करने से डायरिया, पेट संबंधी संक्रमण सहित विभिन्न संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। साबुन और स्वच्छ पानी से सही तरीके से हाथ धोने की आदत अपनाकर इन बीमारियों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।



भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने पर दिया जोर

जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भोजन करने से पहले, शौच के बाद तथा गंदगी के संपर्क में आने पर साबुन और स्वच्छ पानी से हाथ धोने की आवश्यकता बताई गई। साथ ही हाथ धोने के दौरान हथेलियों, हाथों के पिछले हिस्से, उंगलियों के बीच तथा नाखूनों के आसपास अच्छी तरह सफाई करने के महत्व से अवगत कराया गया। बच्चों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने की सलाह दी गई।

स्वच्छता की आदत अपनाने और दूसरों को जागरूक करने का आह्वान

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्वच्छता को अपने दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्हें अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी नियमित हाथ धुलाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।



विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि नियमित हाथ धुलाई जैसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत अपनाकर स्वयं के साथ परिवार और समाज को भी संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने में योगदान दिया जा सकता है।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए प्रकाशक मुद्रक संपादक अभिषेक शर्मा द्वारा शॉप नंबर 33, एक सत बुलेटिन कार्यालय, संजय चौक , गौरेला जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ पिन कोड 495117 से प्रकाशित एवं असमां पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयस्तम्भ चौक रायपुर छत्तीसगढ़ -492001 से मुद्रित। समूह संपादक - महेश कुमार तिवारी , स्थानीय उप संपादक / सिटी चीफ़ - भूपेंद्र सिंह , प्रशांत डेनियल